



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 31, 1986/ज्येष्ठ 10, 1908

No. 217]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 31, 1986/JYAISTHA 10, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह बलग संकलन के रूप में  
रचा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मई, 1986

अधिसूचनाएं

का.भा. 312(अ):—केन्द्रीय सरकार ने, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 17 जुलाई, 1985 की अधिसूचना संख्या का.भा. 527 (अ) के तहत श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में मजदूरी की दरों को नियत या पुनरीक्षित करने के लिए एक मजदूरी बोर्ड गठित किया है;

और उक्त बोर्ड बराबर अपना कार्य कर रहा है;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में मजदूरी की अंतरिम दरें निर्धारित करना आवश्यक है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 13(क) की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मजदूरी बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में वर्तमान मूल वेतन के 15 प्रतिशत की दर से, मजदूरी की अंतरिम दरें नियत करती है, जो न्यूनतम 90/- रु. प्रतिमाह है। इस प्रकार निर्धारित अंतरिम सहायता सभी उद्देश्यों, जिनमें भविष्य निधि अंशदान, कर्मचारी राज्य बीमा, उपदान, बोनस जैसे ग्राह्य लाभों का निर्धारण शामिल है, के लिए मूल मजदूरी का भाग समझी जाएगी।

309 GI/86

(1)

जहां कोई समाचारपत्र स्थापन या तो अपने कर्मचारियों से हुई बातचीत के परिणामस्वरूप या अन्यथा, ऐसे श्रमजीवी पत्रकारों को जो उस समाचारपत्र स्थापन में या उसके संबंध में, उस रूप में नियोजित हैं, अंतरिम सहायता देने के लिए सहमत हो गया है और ऐसी अंतरिम सहायता का संबंध मूल मजदूरी या महंगाई भत्ते से है, ऐसी सहायता की राशि को मजदूरी की दरों में उपर्युक्त वृद्धियों के विरुद्ध समायोजित कर लेना अनुज्ञेय होगा :

परन्तु जहां किसी श्रमजीवी पत्रकार के संबंध में कोई अंतरिम सहायता, जिसे देने के लिए कोई समाचारपत्र स्थापन सहमत हो गया है, मजदूरी की दरों में उपर्युक्त वृद्धि से अधिक है वहां वह अंतरिम सहायता जिस पर समाचारपत्र स्थापन सहमत हो गया है, ऐसे श्रमजीवी पत्रकारों के लिए दी जाएगी (अर्थात् इसमें कमी नहीं की जाएगी और वे ऊपर सिफारिश की गई मजदूरी की दरों की वृद्धि के हकदार नहीं होंगे।

मजदूरी की अंतरिम दरें पहली जून, 1986 से देय होंगी।

[संख्या बी-24032/6/86-वै.म.]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 30th May, 1986

NOTIFICATIONS

S.O. 312 (E):— Whereas the Central Government has, in exercise of the powers conferred by section 9 of the Working Journalists and other Newspaper

Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955), constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 527 (E), dated the 17th July, 1985 a Wage Board for the purpose of fixing or revising the rates of wages in respect of working journalists;

And whereas the said Board continues to function;

And whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to fix interim rates of wages in respect of working journalists:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 13A, of the said Act, the Central Government, after consultation with the Wage Board, hereby fixes the interim rates of wages in respect of working journalists at the rate of 15 per cent of the existing basic wages subject to a minimum of Rs. 90/- p.m. The interim relief thus fixed shall be taken as part of the basic wages for all purposes including determination of admissible benefits such as contribution to Provident Fund, Employees State Insurance, Gratuity, Bonus, etc.

Where any newspaper establishment has either as a result of negotiations with its employees or otherwise agreed to pay interim relief to working journalists employed as such in or in relation to, such newspaper establishment, and such interim relief is related to the basic wages or to the dearness allowance, it shall be permissible, to adjust the amount of such relief against increases in the rates of wages made above:

Provided that where the interim relief agreed to be paid by any newspaper establishment, in respect of any working journalists is in excess of the increase in the rates of wages made above, such interim relief agreed to by the newspaper establishment shall continue to be paid (i.e., it shall not be reduced) in respect of such working journalists and they shall not be entitled, in addition, to the increase in rates of wages recommended above.

The interim rates of wages shall be payable with effect from 1st June, 1986.

[F. No. V-24032/6/86-W. B.]

का आ 313(अ) —केन्द्रीय सरकार ने, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (मेवा की शर्तों) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 13ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय की तारीख 17 जुलाई, 1985 की अधिसूचना मध्या का आ. 528 (अ) के तहत गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी दरें नियत करने या पुनरीक्षित करने के लिए एक मजदूरी बोर्ड गठित किया है;

और उक्त बोर्ड बराबर अपना कार्य कर रहा है,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी की अंतरिम दरें निर्धारित करना आवश्यक है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 13(घ) के साथ पठित धारा 13क की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मजदूरी बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के संबंध में मूल वेतन के 15 प्रतिशत की दर से मजदूरी की अंतरिम दरें नियत करती है जो न्यूनतम 90/- रुपये प्रतिमाह हों। यह अंतरिम सहायता सभी उद्देश्यों, जिसमें श्रम विधि अशदान, कर्मचारी राज्य बीमा, उपदान, बोनस, आदि जैसे ग्राह्य लाभों का निर्धारण शामिल है, के लिए मूल मजदूरियों का भाग समझी जाएगी।

जहां कोई समाचारपत्र स्थापन, या तो अपने कर्मचारियों से हुई बातचीत के परिणामस्वरूप या अन्यथा, ऐसे गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों का, जो उस समाचारपत्र स्थापन में, या उसके संबंध में, उस रूप में नियोजित है, अंतरिम सहायता देने के लिए सहमत हो गया है और ऐसी अंतरिम सहायता का संबंध मूल मजदूरी या महगाई भत्ते से है, ऐसी सहायता की राशि को मजदूरी की दरों में उपर्युक्त वृद्धियों के विरुद्ध समायोजित कर लेना अनुज्ञेय होगा

परन्तु जहां किसी गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए कोई अंतरिम सहायता, जिसे देने के लिए कोई समाचारपत्र स्थापन सहमत हो गया है, मजदूरी की दरों में उपर्युक्त वृद्धि से अधिक है, वहां वह अंतरिम सहायता जिस पर समाचारपत्र स्थापन सहमत हो गया है, ऐसे गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए दी जाएगी (अर्थात् इसमें कमी नहीं की जाएगी) और वे ऊपर सिफारिश की गई मजदूरी की दरों की वृद्धि के हकदार नहीं होंगे।

मजदूरी की अंतरिम दरें पहली जून, 1986 से देय होंगी।

[वी 24032/6/86-वे में ]

ए. के. टण्डन, सयुक्त सचिव

S.O. 313(E):— Whereas the Central Government has, in exercise of the powers conferred by section 13C of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955), constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 528 (E) dated the 17th July, 1985 a Wage Board for the purpose of fixing or revising the rates of wages in respect of Non-Journalists Newspaper Employees;

And whereas the said Board continues to function;

And whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to fix interim rates of wages in respect of Non-Journalist Newspaper Employees;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 13A, read with section 13(D) of the said Act, the Central Government

after consultation with the Wage Board, hereby fixes the interim rates of wages in respect of Non-Journalist Newspaper employees at the rate of 15 per cent of basic wages subject to a minimum of Rs. 90/- p.m. The interim relief shall be taken as part of the basic wages for all purposes including determination of admissible benefits such as contribution to Provident Fund, Employees State Insurance, Gratuity, Bonus, etc.

Where any newspaper establishment has either as a result of negotiations with its employees or otherwise agreed to pay interim relief to Non-journalist Newspaper Employees employed as such in or in relation to, such newspaper establishment, and such interim relief is related to the basic wages or to the dearness allowance, it shall be permissible, to

adjust the amount of such relief against increases in the rates of wages made above:

Provided that where the interim relief agreed to be paid by any newspaper establishment, in respect of any Non-journalist Newspaper Employees is in excess of the increase in the rates of wages made above, such interim relief agreed to by the newspaper establishment shall continue to be paid (i.e., it shall not be reduced) in respect of such Non-Journalist Newspaper Employees and they shall not be entitled, in addition, to the increase in rates of wages recommended above.

The interim rates of wages shall be payable with effect from 1st June, 1986.

[F. No. V-24032/6/86—W.B.]  
A.K. TANDON, Jt. Secy.

